पत्र सूचना कार्यालय (विंग रक्षा)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली: कार्तिक 23, 1944
सोमवार: 14 नवंबर 2022

त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने के साथ वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सशस्त्र बलों की समाघात तत्परता के लिए महत्वपूर्ण: नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग से कहा

श्री राजनाथ सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं को और विकसित करने; आंतरिक सतर्कता रचनातंत्र को मजबूत करने और बेहतर परिणामों के लिए कार्यबल कौशल में वृद्धि करने का आह्वान किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) से त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने के माध्यम से वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह सशस्त्र बलों की समाघात तत्परता को मजबूत करने की कुंजी है। रक्षा लेखा विभाग के दो दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन का 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को रक्षा वित्त प्रणाली के प्रहरी के रूप में वर्णित किया, जो वित्तीय विवेक के साथ आवंटित धन का प्रबंधन करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।

रक्षा लेखा विभाग रक्षा मंत्रालय को आवंटित बजट की देखरेख करते हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यभार सहित अन्य सहायक गतिविधियों के अलावा कार्मिकों के वेतन और भत्ते, पेंशनभोगियों को भुगतान, विभिन्न अधिप्राप्तियों के लिए वित्तीय सलाह मामलों का प्रसंस्करण और प्रथम तथा तीसरे पक्ष के दावों को प्रक्रम में परिवर्तित करता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं।

सम्मेलन के एजेंडा बिंदुओं में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन: फेसलेस लेनदेन की एक प्रणाली की ओर; आईएफए प्रणाली: प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक साधन; दक्षता और प्रदर्शन लेखा परीक्षा: अनुपालन से आश्वासन रूपरेखा तक; सेवा वितरण में सुधार; रक्षा लेखा विभाग द्वारा विकसित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को चालू रखना और मानव संसाधन में चुनौतियां शामिल है।

श्री राजनाथ सिंह ने लाभार्थियों, अर्थात सैनिकों, पेंशनभोगियों और तीसरे पक्ष को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि 'सार्वजनिक वित्त प्रबंधन: फेसलेस लेनदेन की एक प्रणाली की ओर' पर आधारित सत्र रक्षा वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन रक्षा लेखा विभाग की सेवाओं में सुधार; इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूत करेगा।

'आईएफए प्रणाली की दक्षता: प्रभावी निर्णय लेने का एक साधन' विषयवस्तु पर सत्र वित्तीय सलाहकारों को वित्तीय शक्तियों के नवीनतम प्रत्यायोजन के साथ पेश करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सत्र से सलाहकारों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और निर्णय लेने से संबंधित मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए ग्राहक की जरूरतों की संवेदनशील समझ के साथ सहयोगी अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञता आवश्यक है। उन्होंने नियंत्रकों से आग्रह किया कि वे एक सहयोगी की मानसिकता के साथ और दोनों पक्षों के लाभ के लिए काम करें।

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं और वित्तीय ज्ञान को और विकसित करने; आंतरिक सतर्कता रचनातंत्र को मजबूत करने और अपने कर्तव्यों का अधिक कुशलता से निर्वहन करने के लिए अपने कार्यबल के कौशल को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "अगर किसी अधिकारी के कामकाज में संदेह है तो उसकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए. शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। यदि शिकायतें लंबित हैं, तो उनके साप्ताहिक या मासिक ऑडिट के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए।"

https://twitter.com/rajnathsingh/status/1592029767015899137

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग के 275 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और एक विशेष कवर एनवेलप जारी किया। उद्घाटन सत्र में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री विजय कुमार सिंह, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) श्रीमती रसिका चौबे और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सुश्री मंजू कुमार ने भाग लिया।

हर दो-तीन साल में समय-समय पर आयोजित होने वाला सम्मेलन रक्षा लेखा विभाग और रक्षा मंत्रालय को विभिन्न मुद्दों का जायजा लेने, विचार-विमर्श करने और टिकाऊ समाधानों पर पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष देश भर से 100 से अधिक प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रकों (पीसीडीए)/रक्षा लेखा नियंत्रकों (सीडीए)/एकीकृत वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) की भागीदारी देखी जा रही है।

एबीबी/डीएस